

बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति और समाधान

डॉ. हेमा तिवारी

सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
श्याम शिक्षा महाविद्यालय सक्ती

सारांश (Abstract)

बालिका शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का मूल आधार है। एक शिक्षित लड़की न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन दर बढ़ा है, किंतु माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर उनकी उपस्थिति अभी भी अपेक्षाकृत कम है। सामाजिक कुरीतियाँ, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी और अभिभावकों की उदासीनता जैसी समस्याएँ बालिका शिक्षा में प्रमुख बाधाएँ हैं।

सरकार ने बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, समग्र शिक्षा अभियान और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई योजनाएँ लागू की हैं, जिनसे सकारात्मक परिणाम मिले हैं। साथ ही विद्यालयों में अवसंरचना सुधार, सुरक्षित परिवहन, छात्रवृत्ति योजनाएँ और डिजिटल शिक्षा जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं।

फिर भी बालिका शिक्षा की स्थिति को और सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक जागरूकता, अभिभावकों की मानसिकता में परिवर्तन और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। जब प्रत्येक बालिका को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी तभी महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और राष्ट्र का समग्र विकास संभव हो सकेगा।



बीज शब्द (Keywords)

बालिका शिक्षा, लैंगिक समानता, साक्षरता दर, सामाजिक कुरीतियाँ, सरकारी योजनाएँ, महिला सशक्तिकरण।

प्रस्तावना (Introduction)



शिक्षा किसी भी समाज के विकास की रीढ़ है। यह न केवल व्यक्तिगत ज्ञान और कौशल का विकास करती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी आधार है। विशेष रूप से बालिका शिक्षा समाज में परिवर्तन और प्रगति का सबसे प्रभावी साधन है। एक शिक्षित लड़की न केवल स्वयं सशक्त होती है बल्कि अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा एवं जागरूकता का मार्ग दिखाती है।

यही कारण है कि कहा गया है – “यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, किंतु यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है।”

भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति स्वतंत्रता से पहले बहुत दयनीय थी। सामाजिक कुरीतियाँ, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज जैसी परंपराओं के कारण लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और स्त्री-पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान किए। धीरे-धीरे सरकारी नीतियों और सामाजिक जागरूकता के कारण बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति हुई है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अब अनेक क्षेत्रों में लड़कियाँ लड़कों से आगे निकल रही हैं।

फिर भी वास्तविकता यह है कि आज भी भारत के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में बालिका शिक्षा कई चुनौतियों का सामना कर रही है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर ड्रॉपआउट दर अधिक है। आर्थिक कठिनाइयाँ, सुरक्षा की कमी, सामाजिक भेदभाव, अवसरचनना की समस्याएँ और अभिभावकों की मानसिकता बालिकाओं की शिक्षा में बाधा बन रही हैं। सरकार ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएँ चलाई हैं जैसे— बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सुकन्या समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा अभियान आदि। इन प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं, लेकिन अभी भी हर बेटे तक शिक्षा का प्रकाश पहुँचाने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर और सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझना और उसकी चुनौतियों का समाधान खोजना एक आवश्यक कार्य है, क्योंकि यह केवल बालिकाओं का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के विकास का प्रश्न है।

अध्ययन की आवश्यकता (Need of the Study)

- ✧ समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना।
- ✧ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की असमानताओं को दूर करना।
- ✧ सामाजिक कुरीतियों (बाल विवाह, दहेज) को शिक्षा के माध्यम से समाप्त करना।
- ✧ राष्ट्रीय विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

उद्देश्य (Objectives)

- ✧ बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।

- ✧ बालिका शिक्षा में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना।
- ✧ सरकारी योजनाओं और नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- ✧ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाधान प्रस्तुत करना।

बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति

भारत में महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी यह पुरुषों की तुलना में कम है। यदि ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा की समान सुविधा मिले, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जाए और सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो, तो महिला साक्षरता दर में और वृद्धि होगी और भारत पूर्णतः साक्षर समाज बनने की ओर अग्रसर होगा।

1. साक्षरता दर (Literacy Rate)— साक्षरता दर किसी भी देश के विकास का प्रमुख सूचकांक है। यह दर यह दर्शाती है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में से कितने लोग पढ़ना-लिखना जानते हैं।

भारत में महिला साक्षरता दर का परिदृश्य

1. ऐतिहासिक स्थिति

- ✧ स्वतंत्रता से पहले भारत में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी (1901 में केवल 1% से भी कम)।
- ✧ सामाजिक कुरीतियाँ (बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज) और गरीबी लड़कियों को शिक्षा से वंचित करती थीं।

2. जनगणना 2011 के अनुसार

- ✧ कुल साक्षरता दर— 74.04%
- ✧ पुरुष साक्षरता दर— 82.14%
- ✧ महिला साक्षरता दर— 65.46%

☞ इससे स्पष्ट है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच लगभग 17% का अंतर है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य

- ✧ सभी बच्चों और वयस्कों को 100% साक्षरता की ओर ले जाना।
- ✧ विशेष ध्यान —बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों पर।

4. नवीनतम रिपोर्ट (नवम्बर 2021-22 और जून 2021-22)

- ✧ प्राथमिक स्तर (Class I-V)— लड़कियों का नामांकन दर (GER) लगभग 95% से अधिक है।
- ✧ माध्यमिक स्तर (Class VI-VIII)— लड़कियों का नामांकन 90% से ऊपर है।
- ✧ उच्च शिक्षा— भारत की कुल उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों में 49% बालिकाएँ हैं।

☞ इसका अर्थ है कि उच्च शिक्षा में अब बालिकाओं की भागीदारी लगभग बराबरी पर पहुँच रही है।

राज्यवार स्थिति

केरल— सबसे अधिक महिला साक्षरता दर (95% से अधिक)।

बिहार और राजस्थान— सबसे कम महिला साक्षरता दर (लगभग 60-65%)।

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कमजोर है, जबकि शहरी क्षेत्रों में सुधार दिख रहा है।

ग्रामीण और शहरी अंतर

- ✧ शहरी क्षेत्र: महिला साक्षरता दर लगभग 80% तक पहुँच गई है।
- ✧ ग्रामीण क्षेत्र: महिला साक्षरता दर अभी भी 60-65% के आसपास है।

☞ इसका कारण है— संसाधनों की कमी, विद्यालयों की दूरी, अभिभावकों की मानसिकता और आर्थिक कठिनाई।

2. विद्यालय नामांकन (Enrollment of Girls)— विद्यालय नामांकन (Enrollment) से आशय है— किसी निश्चित आयु वर्ग के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश और अध्ययनरत रहना। यह शिक्षा की पहुँच और समानता का प्रमुख संकेतक है।

भारत में बालिकाओं का विद्यालय नामांकन— वर्तमान स्थिति— 1. प्राथमिक स्तर (Class I – V)— हाल के वर्षों में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन लगभग 95: से अधिक (GER – Gross Enrollment Ratio) है।

- ✧ कई राज्यों में प्राथमिक स्तर पर लड़कियाँ लड़कों से भी अधिक संख्या में नामांकित हो रही हैं।
- ✧ मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पुस्तकें, गणवेश और छात्रवृत्तियाँ इसके प्रमुख कारण हैं।

2. उच्च प्राथमिक स्तर (Class VI – VIII)

- ✧ इस स्तर पर लड़कियों का नामांकन लगभग 90% है।
- ✧ परंतु यहाँ से ड्रॉपआउट दर बढ़ने लगती है।

कारण—

- ✧ किशोरावस्था से जुड़ी समस्याएँ
- ✧ विद्यालयों में शौचालय और सुरक्षा की कमी
- ✧ घरेलू जिम्मेदारियाँ और आर्थिक स्थिति

3. माध्यमिक स्तर (Class IX – X)

- ✧ इस स्तर पर नामांकन दर घटकर लगभग 77-80: रह जाती है।
- ✧ बाल विवाह, परिवार की आर्थिक स्थिति और पढ़ाई के प्रति समाज की उदासीनता इसके बड़े कारण हैं।
- ✧ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थिति अधिक चिंताजनक है।

4. उच्च माध्यमिक स्तर (Class XI – XII)

- ✧ यहाँ नामांकन दर और भी कम होकर लगभग 55-60% रह जाती है।
- ✧ कई बालिकाएँ इस स्तर तक पहुँचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देती हैं।

5. उच्च शिक्षा (College / University)

- ✧ AISHE Report 2021-22 के अनुसार, भारत की कुल उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों में लगभग 49% बालिकाएँ हैं।
- ✧ उच्च शिक्षा में लड़कियाँ लगभग बराबरी की स्थिति में पहुँच चुकी हैं।
- ✧ चिकित्सा, कला, वाणिज्य और शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की संख्या अधिक है, जबकि इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में अभी भी वे कम हैं।

राज्यवार स्थिति

केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली— यहाँ बालिकाओं का नामांकन दर अधिक है।

बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड— यहाँ माध्यमिक स्तर के बाद लड़कियों का नामांकन तेजी से घटता है।

सरकारी योजनाओं का प्रभाव

- ✧ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)— पिछड़े और ग्रामीण इलाकों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय।
- ✧ समग्र शिक्षा अभियान— प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक शिक्षा को बढ़ावा।
- ✧ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना— समाज को जागरूक कर नामांकन बढ़ाने का प्रयास।
- ✧ मध्याह्न भोजन योजना— अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन।
- ✧ मुफ्त गणवेश और छात्रवृत्ति— आर्थिक सहयोग से लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने में मदद।

3. ड्रॉपआउट दर (Dropout Rate of Girls)— ड्रॉपआउट दर का अर्थ है दृ विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी का अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले पढ़ाई छोड़ देना। यह शिक्षा की निरंतरता और उपलब्धता का महत्वपूर्ण संकेतक है।

भारत में बालिकाओं की ड्रॉपआउट दर— स्थिति

1. प्राथमिक स्तर (Class I – V)

- ✧ इस स्तर पर लड़कियों की ड्रॉपआउट दर बहुत कम है।
- ✧ लगभग 1-3% बालिकाएँ प्राथमिक स्तर से आगे नहीं बढ़ पातीं।

✧ इसका मुख्य कारण अभिभावकों का प्रारंभिक स्तर तक ही शिक्षा को पर्याप्त समझना है।

2. उच्च प्राथमिक स्तर (Class VI – VIII)

इस स्तर पर लड़कियों की ड्रॉपआउट दर बढ़कर 6–7% तक पहुँच जाती है।

कारण

- ✧ किशोरावस्था में स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याएँ
- ✧ विद्यालयों में शौचालय और स्वच्छता की कमी
- ✧ घरेलू कार्यों और छोटे भाई-बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी

3. माध्यमिक स्तर (Class IX – X)

इस स्तर पर लड़कियों की ड्रॉपआउट दर सबसे अधिक होती है दृ लगभग 15दृ18:।

कारण—

- ✧ आर्थिक कठिनाइयाँ (पढ़ाई के खर्च का बोझ)
- ✧ परिवारों में बाल विवाह की परंपरा
- ✧ सुरक्षा और परिवहन की समस्या
- ✧ अभिभावकों का यह मानना कि “लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं”

4. उच्च माध्यमिक स्तर (Class XI – XII)

- ✧ इस स्तर पर ड्रॉपआउट दर 20% से अधिक हो जाती है।
- ✧ अधिकांश लड़कियाँ विवाह या घरेलू जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं।
- ✧ ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है।

ड्रॉपआउट के प्रमुख कारण

1. सामाजिक कारण

- ✧ बाल विवाह, दहेज प्रथा और लैंगिक भेदभाव
- ✧ “लड़की को पढ़ाकर क्या करना है” जैसी सोच

2. आर्थिक कारण

- ✧ परिवार की गरीबी और शिक्षा का खर्च
- ✧ लड़कियों से घरेलू कार्य की अपेक्षा

3. शैक्षणिक कारण

- ✧ विद्यालयों में शौचालय और सुरक्षा की कमी
- ✧ विद्यालय की दूरी और परिवहन का अभाव
- ✧ महिला शिक्षकों की कमी
- ✧ मनोवैज्ञानिक कारण
- ✧ आत्मविश्वास की कमी
- ✧ किशोरावस्था की समस्याएँ
- ✧ परिवार और समाज का दबाव

सरकारी पहल ड्रॉपआउट कम करने के लिए

1. **समग्र शिक्षा अभियान** – गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नामांकन बनाए रखने हेतु।
2. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)** – पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय।
3. **मध्याह्न भोजन योजना** – बच्चों को विद्यालय आकर्षित करने का प्रयास।
4. **छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएँ** – आर्थिक सहयोग से पढ़ाई जारी रखने में मदद।
5. **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना** – बालिका शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता।

4. सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएँ— सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएँ वे अवरोध हैं जो समाज की परंपराओं, मान्यताओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक धारणाओं के कारण बालिकाओं की शिक्षा में उत्पन्न होते हैं। ये बाधाएँ प्रायः मानसिकता, परंपराओं और लैंगिक असमानता से जुड़ी होती हैं।

बालिका शिक्षा में प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएँ—

1. लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination)

- ✧ परंपरागत सोच— “लड़के कमाएँगे, लड़कियाँ घर संभालेंगी”
- ✧ शिक्षा में निवेश लड़कों पर अधिक, लड़कियों पर कम।
- ✧ परिवार का मानना कि लड़कियों को अधिक पढ़ाई की आवश्यकता नहीं।

2. बाल विवाह (Child Marriage)

- ✧ अभी भी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह प्रचलित है।
- ✧ विवाह के बाद पढ़ाई अधूरी रह जाती है।
- ✧ UNESCO रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हजारों लड़कियाँ हर साल विवाह के कारण शिक्षा छोड़ देती हैं।

3. सामाजिक सुरक्षा की समस्या

- ✧ विद्यालय की दूरी, परिवहन का अभाव, छेड़छाड़ और असुरक्षा की भावना।
- ✧ अभिभावक बेटियों को दूर के विद्यालय भेजने से हिचकिचाते हैं।

4. सांस्कृतिक परंपराएँ

- ✧ रूढ़िवादी परिवारों में यह मान्यता प्रबल है कि लड़कियों का मुख्य कार्य घरेलू जिम्मेदारी निभाना है।
- ✧ कुछ समुदायों में लड़कियों की पढ़ाई को सामाजिक रूप से महत्व नहीं दिया जाता।

5. घरेलू जिम्मेदारियाँ

- ✧ घर के कामकाज, छोटे भाई-बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी लड़कियों पर डाल दी जाती है।
- ✧ इस वजह से उनकी पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पाती।

6. धार्मिक और जातिगत मान्यताएँ

- ✧ कुछ स्थानों पर धार्मिक मान्यताओं के कारण लड़कियों की शिक्षा पर रोक या सीमाएँ लगाई जाती हैं।
- ✧ जातिगत भेदभाव भी लड़कियों की शिक्षा में अवरोध बनता है।

7. सामाजिक प्रतिष्ठा और दहेज प्रथा

- ✧ कई परिवार सोचते हैं कि “लड़की ज्यादा पढ़ जाएगी तो शादी में कठिनाई होगी”।
- ✧ दहेज पर अधिक ध्यान दिया जाता है, शिक्षा पर कम।

इन बाधाओं के प्रभाव

- ✧ लड़कियों की ड्रॉपआउट दर बढ़ती है।
- ✧ उच्च शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी घटती है।
- ✧ लैंगिक असमानता बनी रहती है।
- ✧ समाज में महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति कमजोर रहती है।

समाधान

1. जागरूकता अभियान— समाज में शिक्षा के महत्व पर जोर।
2. कानूनी प्रावधानों का पालन— बाल विवाह निषेध, शिक्षा का अधिकार अधिनियम।
3. महिला सुरक्षा उपाय— सुरक्षित परिवहन, विद्यालयों में अलग शौचालय, सीसीटीवी।
4. सकारात्मक सोच का विकास— लड़कियों को परिवार और समाज में समान अवसर।
5. महिला शिक्षकों की नियुक्ति— जिससे अभिभावकों का विश्वास बढ़े।

5. सरकारी प्रयास और योजनाएँ (Government Efforts – Schemes for Girl Education)

भारत सरकार और राज्य सरकारों ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनका उद्देश्य है—

- ✧ लड़कियों के लिए शिक्षा को सुलभ, सस्ती और सुरक्षित बनाना,
- ✧ नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना,
- ✧ ड्रॉपआउट दर कम करना,
- ✧ और समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना।

प्रमुख सरकारी प्रयास और योजनाएँ

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020)

- ✧ शिक्षा में लैंगिक समानता और समावेशिता पर जोर।
- ✧ Gender Inclusion Fund की स्थापना, जिससे बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।
- ✧ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा अनिवार्य करने का लक्ष्य।

2. समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan)

- ✧ प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक शिक्षा को जोड़ने वाला व्यापक कार्यक्रम।
- ✧ इसमें लड़कियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।
- ✧ बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुविधाएँ।

3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

- ✧ 2004 से शुरू, विशेषकर पिछड़े एवं ग्रामीण इलाकों की लड़कियों के लिए।
- ✧ आवासीय विद्यालय जहाँ गरीब और वंचित वर्ग की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और रहने की सुविधा दी जाती है।

4. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना

- ✧ 2015 में शुरू, उद्देश्य— लड़कियों के जन्म, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- ✧ स्लोगन— “बेटी बोझ नहीं, गर्व है।”
- ✧ इसका प्रभावशाली समाज में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी।

5. मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)

- ✧ विद्यालयों में मुफ्त पौष्टिक भोजन की सुविधा।
- ✧ गरीब परिवारों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन।
- ✧ इससे बालिकाओं का नामांकन और उपस्थिति बढ़ी।

6. राष्ट्रीय प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (National Scheme of Incentives to Girls)

- ✧ 9वीं कक्षा में नामांकन लेने वाली अनुसूचित जाति/जनजाति की लड़कियों को प्रोत्साहन राशि।
- ✧ उद्देश्य— उन्हें माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित करना।

7. सुकन्या समृद्धि योजना

- ✧ बालिकाओं के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा हेतु बचत योजना।
- ✧ परिवारों को बालिका की पढ़ाई और विवाह हेतु आर्थिक सहयोग।

8. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE, 2009)

- ✧ 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा।
- ✧ इसका सबसे बड़ा लाभ बालिकाओं को मिला।

9. सवित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना (कुछ राज्यों में लागू)

- ✧ गरीब परिवारों की लड़कियों को छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएँ।
- ✧ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस योजना से हजारों बालिकाओं को लाभ।

इन प्रयासों के प्रभाव

- ✧ प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन लगभग सार्वभौमिक हो चुका है।

- ✧ उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी अब लगभग 49: तक पहुँच गई है।
- ✧ ड्रॉपआउट दर में कमी आई है, परंतु माध्यमिक स्तर पर अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ अभी भी शेष

- ✧ ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह और गरीबी।
- ✧ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर उच्च ड्रॉपआउट दर।
- ✧ सुरक्षा और परिवहन की कमी।

निष्कर्ष

बालिका शिक्षा केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। जब बेटियाँ शिक्षित होंगी, तभी वे आत्मनिर्भर बनेंगी, परिवार सशक्त होगा और समाज व देश का समग्र विकास संभव होगा।

“एक शिक्षित बालिका, दो पीढ़ियों को शिक्षित करती है।”

भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति पिछले वर्षों में बेहतर हुई है। साक्षरता दर, विद्यालय नामांकन और उच्च शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। सरकारी योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि ने सकारात्मक प्रभाव डाला है। फिर भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की ड्रॉपआउट दर, बाल विवाह, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, सुरक्षा और सामाजिक परंपराएँ आज भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। यदि समाज की सोच में परिवर्तन लाया जाए, परिवार और समुदाय लड़कियों को सहयोग दें तथा सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो, तो बालिका शिक्षा की स्थिति और सशक्त होगी। वास्तव में, एक शिक्षित बालिका न केवल स्वयं के जीवन को संवारती है बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रगति की ओर अग्रसर करती है। इसलिए बालिका शिक्षा को राष्ट्र के विकास की आधारशिला मानकर आगे बढ़ाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। "नई शिक्षा नीति 2020"। नई दिल्ली।
2. भारत सरकार। "समग्र शिक्षा अभियान – दिशा-निर्देश", शिक्षा मंत्रालय, 2022।
3. भारत सरकार। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना – वार्षिक रिपोर्ट", महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2021।
4. यूनेस्को। "Education for All Global Monitoring Report", 2020।
5. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)। "भारतीय शिक्षा परिदृश्य", नई दिल्ली, 2019।
6. योजना आयोग। "भारत में बालिका शिक्षा: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ", योजना रिपोर्ट, 2018।
7. AISHE Report (All India Survey on Higher Education), भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, 2021–22।
8. UNICEF। "Girl's Education in India – Status and Progress", 2020।
9. डॉ. कौल, वी. एन. "भारतीय शिक्षा प्रणाली और लैंगिक समानता", नई दिल्ली: शारदा प्रकाशन, 2017।
10. मिश्रा, राकेश। "महिला शिक्षा: चुनौतियाँ और संभावनाएँ", प्रयागराज: गंगा पब्लिकेशन, 2016।
11. शर्मा, सीमा। "भारतीय समाज में बालिका शिक्षा"। जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2015।
12. World Bank Report। "Secondary Education and Gender Equality in India", 2019।